(ग) वर्तमान में इस्पात का सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितना वाणिज्यिक उत्पादन हुआ;

(घ) क्या आज भी देश इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस्पात के आयात को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) सरकार इस्पात का आयात नहीं करती है। नीति के अनुसार इस्पात का आयात स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति है। चालू वर्ष (अप्रैल-सितंबर, 98) के दौरान आयात किए गए इस्पात की कुल मात्रा और मूल्य (अनंतिम) निम्नानुसार थाः—

मात्रा (हजार टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
35.2	88.61

यह आयात यू॰के॰, रूस, स्वीडन, जर्मनी, सी॰ आई॰ एस॰ देश, इटली, जापान, अर्जेन्टीना, यू॰ एस॰ ए॰, कोरिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों से किया गया था। चालू वर्ष के दौरान जिन क्षेत्रों ने इस्पात का आयात किया उनमें रक्षा, रेलवे, विद्युत, पत्तन और शिपयार्ड घाटे में चल रहा इस्पात उद्योग और ऑटोमोबाइल शामिल है

(ग) चालू वर्ष (अप्रैल, 98-जनवरी, 99) के दौरान परिसज्जित (कार्बन) इस्पात का का कुल उत्पादन निम्नानुसार थाः—

सरकारी क्षेत्र	62.3 लाख टन
निजी क्षेत्र	125.2 लाख टन
योग	187.5 लाख टन

(घ) से (ङ) इस समय अधिकांश इस्पात मदों की कोई कमी नहीं है। फिर भी, किसी भी देश के लिए सभी श्रेणियों / विशिष्टताओं और गुणवत्ता के इस्पात का उत्पादन करना न लागत प्रभावी है और न ही लाभकारी है। विशेष रूप से जब अपेक्षित मात्रा अपेक्षाकृत कम हो। इस्पात के उत्पादक बाजार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने उत्पाद मिश्र को निरन्तर बाजारोन्मुखी बना रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए सेल के इस्पात संयंत्रों और निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार का कार्य शुरू कर दिया गया है। मौजूदा नीति के अनुसार इस्पात की सभी मदों का आयात स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति है।

Bilateral agreement between SAIL and CIL

1365. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether a bilateral agreement has been signed between the Steel Authority of India Ltd. and the Coal India Ltd. regarding supply of coking coal by CIL to SAIL;

(b) if so, what are the terms of the agreement; and

(c) the period of agreement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) Yes, Sir.

(b) Salient terms of agreement relate to quantity, quality, bonus/penalty on ash variation, price in respect of supplies of coking coal from the washeries of BCCL, CCL, WCL and direct supply from BCCL.

(c) The contract period is from 1.1.1998 to 31.3.1999.

Production and export of steel

1366. SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what is the total steel production in the country;

(b) what amount of this production is exported; and

(c) whether Government have any plan of disinvestment of public sector steel plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) and (b) The total production of finished (carbon)

steel in the country and its exports during the last 2 years was as under:—

(In million tonnes)

YEAR	PRODUCTION	EXPORT
1996-97	22.72	1.62
1997-98	23.37	1.82
1998-99 (April, 98-Jan.99)	18.75(Prov)	1.39(Prov)

(c) At present Government has no plans to disinvest of public sector steel plants.

इस्पात उत्पादन का लक्ष्य

1367. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए इस्पात उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है;

(ख) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान इस लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1999-2000 का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) इस्पात उद्योग के उदारीकरण के पश्चात सरकारी और निजी क्षेत्र में इस्पात के मुख्य उत्पादक अपने इस्पात के उत्पादन की योजना मांग-प्रक्षेपण के आधार पर बनाते हैं। देश में परिसज्जित इस्पात की कुल मांग और उपलब्धता के अनुमान विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात द्वारा वार्षिक आधार पर तैयार किए जाते हैं। 1997-98 और 1998-99 के दौरान परिसज्जित (कार्बन) इस्पात की कुल मांग और उत्पादन इस प्रकार रहा:—

(मात्रा: दस लाख टन)

वर्ष	कुल मांग	उत्पादन
1997-98	22.38	22.57 (वास्तविक)
1998-99	24.43	29.11 (प्रक्षेपित)

(ख), (ग) और (ङ) जी, हां। सरकार ने इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार, निजी क्षेत्र में अतिरिक्त इस्पात उत्पादन क्षमताएं सृजित करने को प्रोत्साहित करने के विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाना। इस्पात की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय इस्पात उत्पादक निरंतर उपाय कर रहे हैं जिनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पादकता और उत्पादन में सुधार, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद मिश्र को अपनाना शामिल हैं।

वर्ष 1999-2000 के केन्द्रीय बजट में, सरकार ने विभिन्न उपायों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार पर विशेष बल दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आधारभूत क्षेत्र, सिंचाई परियोजनाएं, आवास परियोजनाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के जल आपूर्ति की योजना का त्वरित विकास शामिल हैं। इन उपायों से इस्पात की मांग में वृद्धि होने की संभावना है।

(घ) उपर्युक्त (ख), (ग) और (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Losses suffered by Rashtriya Ispat Nigam Ltd.

1368. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the losses suffered by the Rashtriya Ispat Nigam Limited during each of the last three years;

(b) the reasons for the losses, if any; and

(c) the steps taken by Government to check such losses?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) The losses/ profits of RINL/VSP during the last three financial accounting years areas